

‘बाँसवाड़ा की धरती पर बिजली उत्पादन में भारत के सामर्थ्य का नया अध्याय लिखा गया है’

प्र.मंत्री मोदी ने नापला में 42,000 करोड़ रुपए की परमाणु बिजली परियोजना के शिलान्यास के दौरान कहा

उदयपुर/बांसवाड़ा, 25 सितम्बर (कांस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, ‘देश आज बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और इस रफ्तार में देश के हर हिस्से, हर राज्य को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि देश विकसित होने के लिए तेज गति से काम

■ प्रधानमंत्री ने परमाणु बिजली परियोजना (42,000 करोड़ रुपए) सहित राजस्थान को 1 लाख 468 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं और वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी।

कर रहा है और इसमें राजस्थान को भी बड़ी भूमिका है।’

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को को नापला (बांसवाड़ा) में माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने देशभर में 1 लाख 22 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को बांसवाड़ा के नापला में आयोजित भव्य समारोह में 1 लाख 22 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल ने साफा पहनाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया तथा विजयस्तंभ का चित्र भेंट किया।

परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। मोदी ने राजस्थान को 42 हजार करोड़ रुपए की परमाणु ऊर्जा परियोजना सहित, 1 लाख 8 हजार 468 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं एवं विकास कार्यों तथा दो

बंदे भारत एक्सप्रेस सहित, तीन नई ट्रेनों की सौगात दी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नवरात्रि के पावन पर्व के दौरान बांसवाड़ा में मां त्रिपुर सुंदरी की धरती पर आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। मोदी

ने कहा कि नवरात्रि में हम शक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और परमाणु ऊर्जा परियोजना के शिलान्यास से बांसवाड़ा की धरती पर ऊर्जा शक्ति, यानी बिजली उत्पादन में भारत के

भूपेन्द्र यादव प.बंगाल में भाजपा के प्रभारी नियुक्त

नई दिल्ली, 25 सितंबर। भाजपा ने गुरुवार को बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए।

पश्चिम बंगाल के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी बनाया

■ धर्मेन्द्र प्रधान को बिहार, ओडिशा सांसद बैजयंत पांडा को तमिलनाडु का प्रभारी नियुक्त किया गया है।

गया है, जबकि त्रिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लव देब सह-प्रभारी होंगे। पश्चिम बंगाल में टीएमपी की मजबूत पकड़ को तोड़ने के लिए की भाजपा यह रणनीति अगम है। वैसे भी अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है। 2026 में होने वाले चुनावों में भूपेंद्र यादव की भूमिका अहम होगी। भूपेंद्र यादव के पास भी अच्छा खासा संगठनात्मक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों से मोदी का संवाद

जयपुर, 25 सितम्बर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर गुरुवार को बांसवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राजस्थान

■ बाँसवाड़ा में आयोजित इस कार्यक्रम में प्र.मंत्री मोदी ने देश भर के लाभार्थियों से बातचीत की।

सहित, देशभर के पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों से संवाद किया।

मोदी ने राजस्थान में फलौदी से पप्पू देवी, कोटपुतली से धर्मेन्द्र कुमार, प्रतापगढ़ से जगदीश मेघवाल, जोधपुर से रामचन्द्र सिंह, भरतपुर से प्रेम सिंह कुंतल, बांसवाड़ा के अर्धुना संघर्ष से संवाद किया।

इस दौरान राज्यपाल हरिभाऊ कसनराव बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी, उपमुख्यमंत्री दिया कुमार एवं डॉ. प्रेमचंद बैरवा तथा सांसद मदन राठीड़ उपस्थित रहे।

सुप्रीम कोर्ट ने दादर-नगर हवेली के 50 साल पुराने भूमि विवाद को निपटाया

–जाल खंबाता–
–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–
नई दिल्ली, 25 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को टिप्पणी की कि औपनिवेशिक युग के भूमि विवाद आज भी भारतीय अदालतों में लंबित हैं, जो चिंताजनक है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी दादर और नगर हवेली में 1923 से 1930 के बीच पुर्तगाली प्रशासन द्वारा दी गई स्थायी पट्टों (एलवरराज) से जुड़े अपीलों पर सुनवाई के दौरान की। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जो पुर्तगाली शासनकाल में जमीन पाने वाले लोगों के वंशजों ने 1974 में कलक्टर द्वारा दी गई कृषि रियायतें रद्द किए जाने के खिलाफ दाखिल की गई थीं। यह कार्रवाई 1919 के “ऑर्गेनिज़ासाओ अग्रारिया” कानून के तहत की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “इस मामले में सबसे चौकाने वाली बात यह नहीं है

भाजपा के सांसदों ने वि.स. चुनाव लड़ने के लिए आनाकानी दिखाई

सूत्रों के अनुसार, भाजपा नेतृत्व ने नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, सतीश दुबे और राजीव प्रताप रूडी आदि को बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा है

–जाल खंबाता–
–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–
नई दिल्ली, 25 सितंबर। बिहार में सतारूढ़ नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस (एनडीए) में एक नया राजनीतिक तुफान उस समय खड़ा हो गया, जब वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य भाजपा मंत्रियों पर जमकर हमला बोला और कथित भ्रष्टाचार के मामलों में कड़ी कार्रवाई की मांग की। उनके बयान ने न केवल प्रदेश इकाई में दरारें और गहरी कर दी हैं, बल्कि आगामी नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को भी असहज कर दिया है।

जनता दल (यूनाइटेड) के नेता और एमएलसी नीरज कुमार, जिन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है, ने भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने गठबंधन के सहयोगियों को याद दिलाया कि नीतीश कुमार का लंबा कार्यकाल स्वच्छ छवि का प्रतीक रहा है, जो चारा घोटाले जैसे घोटालों से भरे अंधकारमय वर्षों से एक स्पष्ट अंतर दिखाता है।

नीरज कुमार ने कहा, “बिहार की जनता ने नीतीश को इस लिए चुना था, क्योंकि वह भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी थी। पिछले दो दशकों से हमने स्वराज और विकास आधारित शासन

■ पर इनमें से अधिकांश ने चुनाव लड़ने से इन्कार कर दिया और कहा कि विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ दाँव पर है, अगर हम हार गए तो यह राजनैतिक आत्महत्या होगी और जीत गए तो भी दिल्ली में प्रभाव कम हो जाएगा।

■ इसी बीच वरिष्ठ भाजपा नेता आर.के. सिंह ने बिहार के उपमुख्यमंत्री, भाजपा के सम्राट चौधरी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और कड़ी कार्यवाही की मांग की।

■ पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि इस बार चुनावों में एनडीए सवालों से घिरा हुआ है।

दिया है। भाजपा नेताओं पर ऐसे आरोप गठबंधन की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाते हैं।”

पटना में उठे इस विवाद ने दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को हिला कर रख दिया है, जो पहले से ही पार्टी कार्यकर्ताओं और सहयोगी दलों के असंतोष से जूझ रहा है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि आंतरिक कलह और भ्रष्टाचार के आरोप एनडीए के “सुशासन” के नैरेटिव को कमजोर कर सकते हैं, जो पिछले चुनावों में इसकी ताकत रहा है।

नर्वस भाजपा नेतृत्व ने कथित रूप से कम से कम पांच केंद्रीय मंत्रियों और प्रमुख सांसदों को बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा है। जिन नामों की चर्चा हो रही है,

उनमें केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह के साथ, वरिष्ठ सांसद राजीव प्रताप रूडी और सतीश दुबे शामिल हैं।

हालांकि, इन नेताओं में से अधिकांश ने राज्य की चुनावी राजनीति में उतरने से अनिच्छा जताई है। सूत्रों के अनुसार, उन्हें डर है कि इतना हाई-स्टेक चुनाव लड़ना उनके लिए राजनीतिक जोखिम साबित हो सकता है।

एक वरिष्ठ भाजपा सांसद ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा, “अगर हार गए तो राजनीतिक आत्महत्या है और अगर जीत भी गए, तो दिल्ली में हमारी पकड़ कमजोर हो जाएगी। किसी भी सूरत में यह हमारे लिए एंडगेम साबित हो सकता है।”

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अगले लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर भारत को सिंधु नदी का पानी मिलेगा?

भारत सरकार सिंधु नदी के सिस्टम में भारी बदलाव करने की दिशा में गंभीर कदम उठा रही है

–जाल खंबाता–
–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–
नई दिल्ली, 25 सितम्बर। भारत, उत्तर भारत की जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सिंधु नदी प्रणाली में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निर्लंबित करने के बाद, अब सरकार इस परियोजना को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरा करने की दिशा में रणनीतिक कदम उठा रही है।

पिछले शुक्रवार को वरिष्ठ मंत्रियों की एक समीक्षा बैठक के दौरान बताया गया कि एक 14 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है, जो सिंधु नदी को ब्यास नदी से जोड़ेगा। ये दोनों नदियाँ सिंधु प्रणाली का हिस्सा हैं। यह जानकारी उन सूत्रों ने दी है जो इस

■ प्रोजेक्ट से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इस संबंध में 14 किलोमीटर लम्बी टनल बनाने के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जो सिंधु नदी को व्यास नदी से जोड़े देगी।

■ बहुराष्ट्रीय कम्पनी लार्सन एण्ड टूब्रो (एलएंडटी) को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया है। ज्ञातव्य है कि 22 अप्रैल के पहलगाम अटैंक के बाद भारत ने सिंधु नदी जल समझौता रद्द कर दिया था, तब से ही केन्द्र सरकार सिंधु नदी का पानी उत्तर भारतीय राज्यों तक पहुँचाने की दिशा में काम कर रही है।

परियोजना से जुड़े हैं।

लार्सन एंड टूब्रो (एल एंड टी) जैसी बहुराष्ट्रीय निर्माण कंपनी को यह परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया है, जो अगले साल तक तैयार होने की उम्मीद है।

सूत्रों ने आगे बताया कि बैठक में, प्रस्तावित 113 किलोमीटर लंबी नहर की भी समीक्षा की गई, जिसके माध्यम से सिंधु जल को उत्तर भारत के राज्यों तक पहुँचाया जाएगा।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

स्कूल के मैदान में रामलीला की अनुमति

नयी दिल्ली, 25 सितंबर। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद स्थित एक स्कूल मैदान में चल रहे रामलीला समारोह को सशर्त जारी रखने की बुधवार को अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति सूर्य कांत, न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयाँ और न्यायमूर्ति एन.

■ सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए फिरोजाबाद के सरकारी स्कूल के मैदान में रामलीला के मंचन की अनुमति दे दी है।

कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के संबंधित आदेश पर रोक लगाते हुए फिरोजाबाद के टूंडला स्थित जिला परिषद विद्यालय मैदान में रामलीला जारी रखने की अनुमति इस

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

–अंजन रॉय–
–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–

नई दिल्ली, 25 सितम्बर। दुनिया भर के बाजारों में अपनी ताकत जमाने की कोशिश करते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप अमेरिका में काम कर रही कंपनियों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। चीन के बेहद सफल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म “टिक टॉक” के भविष्य को लेकर अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय तक चले विवाद के बाद, दोनों देशों ने अमेरिका में टिक टॉक के संचालन को जारी रखने के लिए एक समझौते का फ़ॉर्मूला तय किया। अमेरिका ने पहले कंपनी पर यह शर्त लगाकर कंपनी के अमेरिका में संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया था कि जब तक उसके चीनी मालिक अपनी अमेरिकी संपत्तियाँ अमेरिकी निवेशकों को नहीं बेचते, तब तक टिकटॉक अमेरिका में काम नहीं कर सकेगा। नए

समझौते के अनुसार, अमेरिकी कंपनियों का एक समूह टिकटॉक की अमेरिकी संपत्तियाँ खरीदेगा और उसके मूल एल्गोरिदम को ओरेंकल चलाएगा। इस समझौते के तहत, दोनों देशों के प्रमुख, डॉनल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग, निकट भविष्य में द्विपक्षीय मुद्दों को सुलझाने के लिए मिलने वाले हैं। टिक टॉक को लेकर हुआ यह स्वार्थी समझौता अमेरिकी दावों के खोखलेपन को दर्शाता है, जिनमें वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मुक्त व्यापार वाली अर्थव्यवस्था (फ्री एन्टरप्राइज इकॉनमी) की बात करता है।

अमेरिका एक तरफ तो अपने देश में काम कर रही एक बेहद सफल सोशल

■ अमेरिका ने चीन को मजबूर किया है कि चीन टिक टॉक का अमेरिकन संचालन किसी अमेरिकन कंपनी को बेच दे।

■ जैसा कि विदित है, टिक टॉक विश्व के सबसे सफल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से एक है और अमेरिका के युवाओं में बेहद लोकप्रिय है।

■ अमेरिका इस प्लेटफॉर्म पर न केवल काबिज होना चाहता है, बल्कि यह भी चाहता है कि इसका सॉफ्टवेयर भी अमेरिका में ही बने। चर्चा है कि अमेरिकन कंपनी ऑरेंकल यह सॉफ्टवेयर बनाएगी।

■ इसी नीति के तहत वे अमेरिका में कार्यरत उच्च शिक्षित भारतीय इंजीनियर्स का काम अमेरिकन प्रोफेशनलस को देना चाहते हैं।

■ यह सारी कोशिशें अमेरिका के हित में हो सकती हैं। पर, क्या यह “फ्रीडम ऑफ स्पीच” का उल्लंघन नहीं है, जिसका अमेरिका हमेशा पैरोकार रहा है।

मीडिया कंपनी पर पूरा नियंत्रण चाहता है, और दूसरी ओर भारत जैसे देशों से आने वाले अत्यधिक प्रतिभाशाली तकनीकी पेशेवरों के काम को सीमित करने की कोशिश कर रहा है।

टिक टॉक दुनिया के सबसे सफल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों में से एक रहा है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। लेकिन फिर अमेरिकियों ने आरोप लगाया कि चीनी स्वामित्व वाली यह कंपनी जासूसी कर रही है और ऐप का इस्तेमाल करने वालों तथा अन्य लोगों का निजी डेटा चुरा रहा है।

टिक टॉक पर इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले युवाओं का पसंदीदा प्लेटफॉर्म रहा है, जहाँ वे अपने विचार, राय और गतिविधियाँ साझा करते थे। कुछ लोगों का अनुमान है कि इसके लगभग 4 करोड़ उपयोगकर्ता थे, जिससे यह युवा आबादी पर असर डालने की अનોखी स्थिति में था।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वांगचुक के एनजीओ पर सरकारी शिकंजा

नयी दिल्ली, 25 सितम्बर। सरकार ने लद्दाख के सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोमन वांगचुक के गैर सरकारी संगठन का विदेशी अंशदान नियमन पंजीकरण प्रमाण पत्र (एफसीआरए) बिल्टी

■ केन्द्र सरकार ने वांगचुक के एनजीओ के विदेशी अंशदान नियमन पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है।

अनियमितताओं और कानूनों के उल्लंघन के कारण रद्द कर दिया है। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर कहा कि सक्षम अधिकारी ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम 2010 की धारा 14(1) के तहत अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए वांगचुक के संगठन स्ट्रैटेंस

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

“जीवन के अच्छे दिनों में कभी भी उन लोगों को ना भूले जो जीवन के बुरे दिनों में आपके साथ थे।”

- अरविन्द कटोच

एसआईआर की प्रक्रिया में जारी की जाने वाली मतदाता सूची वास्तव में नागरिक मतदाता सूची है और यह विषय चुनाव आयोग की Autonomy (स्वत्व अधिकार) का है

त्रुटिपूर्ण मतदाता सूचियों को लेकर, अथवा विशेष गहन पुनरीक्षण (1/4SIR1/2) को लेकर, अथवा मतदाता सूचियों से मतदाता का नाम काटने और जोड़ने को लेकर आदि से संबंधित कई आपत्तियों को लेकर चुनाव आयोग पर उनके कर्मचारियों पर पक्षपात करने अथवा तटस्थतहीनता, अवैध आवरण के आरोप लगाये जाकर यहाँ तक कि इन कृत्यों को वोट चोरी के नाम की संज्ञा दी जा रही है। आरोपों का यह सिलसिला यहाँ तक पहुँच गया है कि एनडीए के कई नेताओं ने विपक्ष के नेता पर देश में अशान्ति फैलाने का कृत्य कहा है और यहाँ तक कहा है कि वे देश के युवाओं को व जनरेशन जैड को देश के विरुद्ध भटका रहे हैं। नेताओं का कहना है कि विपक्ष के नेता ने एक्स पर लिखा है “देश के युवा देश के छात्र जेन जैड संविधान को बचायेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे”।

मतदाता सूचियों की अवैधता के उक्त आरोप विपक्ष देश की संसद, देश की सड़कों पर और चुनाव आयोग के कार्यालय में उठा चुके हैं और कई जनहित याचिकायें न्यायालय में पेश की जा रही है, कुछ पर सुनवाई की जा रही है। यद्यपि कोर्ट की कार्यवाही को रोके जाने से अन्तरिम निषेधाज्ञा का आदेश देश कोर्ट ने देने से मना कर दिया है, किन्तु कुछ अन्तरिम आदेश दिये भी हैं। जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि अन्य 11 डॉक्यूमेन्ट्स के साथ नाम जोड़ने में आधार कार्ड का प्रयोग किया जा सकता है, साथ ही यह भी यह भी कहा है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है।

केसेज में सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के अध्ययन ने तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 324, 326, 329 व अन्य प्रावधानों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि न्यायालय के समक्ष दो मूल प्रश्न हैं, प्रथम है क्या एसआईआर पर निर्णय लेना आयोग का विवेकाधिकार है? द्वितीय पक्ष है क्या यह मामला तय करने का अधिकारा अनुच्छेद 32 के तहत पीआईएल में दिया जा सकता है? प्रथम प्रश्न के साथ यह मुद्दा भी विचारणीय है कि जब संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार केवल नागरिक का ही अधिकार है तो फिर अवैध प्रवासियों को जो बांग्लादेश, म्यांमार से आये हुये अवैध माइग्रेन्ट्स हैं, उन्हें एसआईआर की कार्यवाही में कैसे मतदान करने का अधिकार दिया जा सकता है? जबकि नागरिकता तय करने का मापदण्ड अनुच्छेद 6 से 11 में दिया है।

कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है इसे तय करने का अधिकार भारत के गृह मंत्रालय का है। अवैध प्रवासियों में से, जिनके बाबत एसआईआर की कार्यवाही में अवैध प्रवासी हाने की आपत्ति उठाई है, उन्होंने भारत सरकार के समक्ष नागरिकता प्राप्त करने की कार्यवाही नहीं की है। इस प्रकार नागरिकता का प्रश्न भी संवैधानिक प्रश्न है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि अवैध प्रवासियों की जाँच की जावे, उनसे शपथ-पत्र लिया जावे कि उनका जन्म 1 जुलाई, 1987 से पूर्व भारत में हुआ था, विकल्प में उनका जन्म 1 जुलाई, 1987 और दिसम्बर, 2024 के मध्य हुआ है। उनसे उनके माता-पिता के जन्म स्थान के दस्तावेज लिये जावें।

अनुच्छेद 324 में संविधान ने सांसदों व विधायकों की चुनाव की मतदाता सूची तैयार करने का संचालन, अधीक्षण व निदेशन व नियन्त्रण का पूर्ण दायित्व दिया है और अनुच्छेद 326 में स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव में खड़े होने का अधिकार केवल नागरिक को ही है। इसके अतिरिक्त इसी बात को अनुच्छेद 191 में स्पष्ट कर दिया है जबकि मतदाता नागरिक ही नहीं है तो वह विधान सभा का सदस्य होने के लिये और सदस्य चुने जाने के लिये Disqualified (निरहिंत) होगा।

अनुच्छेद 326 एक ओर जहाँ नागरिकों को वयस्क मताधिकार देता है, वहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि मतदाता सूची साधारण सूची नहीं है अपितु नागरिक मताधिकार सूची है। अनुच्छेद 327 में यह व्यवस्था है कि इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुये संसद, राज्य की विधानसभा के लिये चुनाव से सम्बन्धित निर्वाचनों के सभी विषय अर्थात् निर्वाचक नामावली

कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है इसे तय करने का अधिकार भारत के गृह मंत्रालय का है। अवैध प्रवासियों में से, जिनके बाबत एसआईआर की कार्यवाही में अवैध प्रवासी हाने की आपत्ति उठाई है, उन्होंने भारत सरकार के समक्ष नागरिकता प्राप्त करने की कार्यवाही नहीं की है। इस प्रकार नागरिकता का प्रश्न भी संवैधानिक प्रश्न है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि अवैध प्रवासियों की जाँच की जावे, उनसे शपथ-पत्र लिया जावे कि उनका जन्म 1 जुलाई, 1987 से पूर्व भारत में हुआ था, विकल्प में उनका जन्म 1 जुलाई, 1987 और दिसम्बर, 2024 के मध्य हुआ है।

न्यायालय का यह स्पष्ट निर्णय है कि इसका उपयोग मानव अधिकारों के संरक्षण के हेतु ही होना चाहिये न कि अन्य मामलों में। चुनाव सम्बन्धित विषय राजनैतिक है, अतः चुनाव सम्बन्धित विषय के मुकदमों पर अनुच्छेद 32 की याचिकाओं पर सुनवाई करने से इन्कार किया है और यही कारण है कि अनुच्छेद 329 में इस विषय के मुकदमों की सुनवाई केवल चुनाव याचिकाओं के माध्यम से ही की जा सकती है। अनुच्छेद 329 में न्यायालय के हस्तक्षेप के अधिकार को वर्जित किया है सन् 1954 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आज भी मान्य है।

पीआईएल याचिकाओं में पीटीशनर स्वयं का अथवा अन्य विशिष्ट व्यक्ति का, जिसके मूल अधिकार का हनन हुआ है, उसका उल्लेख नहीं है। उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने अपने निर्णय कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, एआईआर 2008 एससी 2116 में यह निर्देश दिया है कि न्याय सक्रियता का अर्थ यह नहीं है कि न्यायापालिका, विधायिका एक कार्यपालिका का कार्य करे। प्रवासी भलाई संगठन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, एआईआर 2014 एससी 1591 में इस बात को स्पष्ट करते हुये कहा है कि न्याय सक्रिया का प्रयोग वहाँ होना चाहिये जहाँ पूर्णतः ऑल्टरनेटिव विधिक शून्यता हो। यहाँ तो अनुच्छेद 329 में चुनाव याचिका में ही मतदाता सूची के विवाद को सुनवाई करने का अधिकार दिया गया है। चुनाव याचिकायें हाईकोर्ट में प्रेषित की जा सकती हैं।

इस प्रकार रिट याचिकाओं के बाबत प्रत्यक्षः उपरोक्त आपत्तियां उठाई जा सकती हैं। मतदान का अधिकार मूल अधिकार नहीं है अपितु संवैधानिक अधिकार है। प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 30 सितम्बर, 2025 तक एसआईआर की फाइनल लिस्ट तैयार हो जावेंगी और 5 अक्टूबर, 2025 को बिहार में चुनाव होने की सूचना जारी होगी तथा 5 से 15 नवम्बर, 2025 के मध्य ये चुनाव होंगे। ऐसी स्थिति में जब चुनाव की सूचना जारी की जा चुकी है तो क्या उक्त पीआईएल स्वतः ही प्राण शून्य हो जावेंगी, क्योंकि उनकी बहस को तारीख ही सम्भवतः 7 अक्टूबर, 2025 है। इस बाबत सुभाष सैनी विरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में सन् 2015 में यह प्रश्न निर्णित हुआ है।

इस प्रकार हम संविधान के परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं कि मतदाता सूची वस्तुतः नागरिक मतदाता सूची है अर्थात् मत देने का अधिकार केवल देश के नागरिक को ही प्राप्त है, यदि वह व्यक्ति नागरिक नहीं है और चुनाव में जीत दर्ज करा देता है तो उसका चुनाव अवैध होगा तथा इसका निर्णय केवल चुनाव याचिका में ही उठाया जा सकता है जिसे सुनने का अधिकार केवल राज्य के हाईकोर्ट को है। चुनाव जीतने के बाद व्यक्ति यदि विधान सभा का सदस्य बन जाता है तो उसकी अयोग्यता का प्रश्न को निर्णय करने का अधिकार केवल राज्य के गवर्नर को प्राप्त है। जिसका निर्णय संविधान के अनुच्छेद 192 के अनुसार होगा। यदि अयोग्य विधायक विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेता है अथवा मत देता है तो उस पर अपराध साबित होने पर प्रतिदिन भाग लेने पर 500/-रूपये जुर्माना किया जा सकता है।

अतः हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि मतदाता सूची केवल नागरिकों को मतदाता सूची इसमें अवैध प्रवासी चाहे वे बांग्लादेश से आये हों अथवा म्यांमार से उन्हें मतदाता में नहीं जोड़ा जा सकता। देश की राजनीति में भाग लेने का अधिकार केवल देश के नागरिकों को ही प्राप्त है। सत्यमेव जयते !

**-अतिथि सम्पादक
पानाचन्द्र जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट**



डॉ. पंकज राजवंशी

यह सारा एच।बी वीजा वाला मामला जब हाल ही में मीडिया में छाया, तो मुझे न चाहते हुए भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आखिर भारतीय अप्रवासियों को लेकर यह असहजता क्यों बढ़ रही है। अमेरिका जैसे देश में, जहाँ आब्रजन का इतिहास गहरा और समृद्ध है, भारतीयों को लेकर यह नया अंतोष आखिर क्यों दिखाई दे रहा है।

मैंने खुद तीस साल पहले अमेरिका में कदम रखा था, वह भी पहली पीढ़ी के प्रवासी के तौर पर। तब की चुनौतियाँ बिल्कुल अलग थीं, संख्या बेहद कम थी और हमें धीरे-धीरे, सम्मानपूर्वक अपना स्थान बनाना था। हमारे जैसे प्रवासी इक्का-दुक्का ही थे और हमारी उपस्थिति खुद एक बयान लगती थी। हम इस नए देश के रंग में ढलना चाहते थे क्योंकि हमें साफ था कि अगर यहाँ सम्मान पाना है, तो पहले इस समाज को समझना और फिर उसका हिस्सा बनना होगा। हमारे लिए समायोजन, यानी, कोई वैचारिक मुद्दा नहीं था बल्कि जीविका और सामाजिक स्वीकृति की बुनियादी शर्त थी। हमने बोलचाल में संयम रखा, शांतिमता बरती और हर सार्वजनिक व्यवहार में सजगता अपनाई। हमारे

त्योहार हों या भाषा, हम यह नहीं चाहते थे कि कोई हमें अलग समझे या हमसे असहज महसूस करे। यह कोई आत्म-समर्पण नहीं था, बल्कि एक आत्म-निर्माण की प्रक्रिया थी जिसे हर प्रवासी को अपने ढंग से अपनाना पड़ता है। उसी ज़मीन पर खड़े होकर जब मैं आज के हालात देखता हूँ, तो मन में एक अजीब सा द्वंद्व उठता है। यही बात मैंने हाल ही में अपनी बेटी से साझा की, और फिर हमारे बीच एक लंबी, जटिल लेकिन ज़रूरी बातचीत हुई।

आज जब मैं हाल के वर्षों में आए भारतीय प्रवासियों को देखता हूँ, खासकर तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को, तो एक बिल्कुल अलग ही रवैया नज़र आता है। बड़े-बड़े समूहों में आकर ये लोग अपने-अपने कस्बों और जिलों को जैसे अमेरिका में दोबारा बसाने लगे हैं। सिफ्टल, डलास, ह्यूस्टन जैसे शहर अब मिनी इंडिया में बदलते जा रहे हैं। वहाँ भारतीय भोजन, भाषा, रीति-रिवाज, परिधान और संगीत सब कुछ बड़े ज़ोर-शोर से मौजूद है। ऐसा लगता है जैसे अब किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं रही। न बोलचाल में कोई सोच-विचार है, न सार्वजनिक व्यवहार में कोई मर्यादा। सार्वजनिक जगहों पर ऊँची आवाज़ में बात करना, बिना अनुमति सामूहिक कार्यक्रम करना, या यह मान लेना कि जिस जगह पर वे हैं वहाँ सब उनके जैसे ही सोचते हैं, यह सब अब सामान्य बात होती जा रही है।

जब मैंने अपनी बेटी से यह सब साझा किया तो उसने कहा, पापा, ये उनका हक है। कोई समाज तय नहीं कर सकता कि प्रवासी कैसे बर्ताव करें। यह मान लेना कि जिस जगह पर वे हैं वहाँ सब उनके जैसे ही सोचते हैं, यह सब अब सामान्य बात होती जा रही है। उनके पास न तो कोई सामाजिक ढांचा था, न तकनीकी सहारे। उन्हें मुख्यधारा में घुलने-मिलने के लिए प्रयास करने पड़ते थे। दूसरी ओर, 2000 के बाद आए प्रवासी ज़्यादातर बड़े समूहों में आए, खासकर तकनीकी क्षेत्र से। उनके पास मंदिर थे, भारतीय टॉर्सरी स्टोर थे, भाषा-समूह थे, और एक समजित डिजिटल नेटवर्क था जिसमें व्हाट्सएप जैसे माध्यम भी शामिल थे। जब आपके चारों ओर इतनी मजबूत सांस्कृतिक बुनियाद हो, तो बाहर की दुनिया से जुड़ने की ज़रूरत कम लगती है। लेकिन इसके साथ ही यह एक ऐसी दीवार भी बन जाती है जो स्थानीय समाज से दूरी पैदा करती है। पहली पीढ़ी के अप्रवासी आत्म-

उसमें खुद को अजनबी महसूस करने लगे? दिलचस्प यह है कि मेरी बेटी भी अब अपने भारतीयपन से जुड़ गई है, लेकिन एक संतुलित तरीके से। वह दिवाली मनाती है, लेकिन शांति से। भारतीय परिधान पहनती है, पर उसका प्रदर्शन नहीं करती। उसकी भारतीय पहचान अब उसके भीतर है, गर्व के साथ लेकिन बिना किसी शोर शराबे के। और यही तो फर्क है। उसकी पीढ़ी, जो यहाँ पैदा हुई, अब अपनी जड़ों से जुड़ना चाहती है लेकिन उसमें दूसरों के लिए सम्मान और एक सजग संतुलन है।

दूसरी ओर, जो लोग भारत से हाल ही में आए हैं, वे सामूहिकता और संख्या के बल पर उस विनम्रता को कहीं पीछे छोड़ आए हैं जो किसी भी प्रवासी समुदाय की सबसे बड़ी ताकत होती है। यह फर्क केवल व्यवहार का नहीं है, यह मानसिकता का भी है। और शायद इसके पीछे का मनोविज्ञान समझने से हम इस पूरी स्थिति को बेहतर समझ पाएँ। 1970 से 1990 के दशक में जो भारतीय अमेरिका आए, वे छोटे-छोटे समूहों में थे।

उनके पास न तो कोई सामाजिक ढांचा था, न तकनीकी सहारे। उन्हें मुख्यधारा में घुलने-मिलने के लिए प्रयास करने पड़ते थे। दूसरी ओर, 2000 के बाद आए प्रवासी ज़्यादातर बड़े समूहों में आए, खासकर तकनीकी क्षेत्र से। उनके पास मंदिर थे, भारतीय टॉर्सरी स्टोर थे, भाषा-समूह थे, और एक समजित डिजिटल नेटवर्क था जिसमें व्हाट्सएप जैसे माध्यम भी शामिल थे। जब आपके चारों ओर इतनी मजबूत सांस्कृतिक बुनियाद हो, तो बाहर की दुनिया से जुड़ने की ज़रूरत कम लगती है। लेकिन इसके साथ ही यह एक ऐसी दीवार भी बन जाती है जो स्थानीय समाज से दूरी पैदा करती है। पहली पीढ़ी के अप्रवासी आत्म-

अस्वीकृति और सामाजिक स्वीकृति के बीच झूलते रहे। वहीं नई पीढ़ी सांस्कृतिक गर्व के साथ जीना चाहती है। टकराव तब होता है जब यह गर्व, दूसरों के लिए दबाव बन जाता है। जब प्रवासी समुदाय छोटे होते हैं, तो उनकी सांस्कृतिक उपस्थिति विविधता लगती है। लेकिन जैसे-जैसे संख्या बढ़ती है, वही उपस्थिति प्रभुत्व जैसी महसूस होने लगती है।

एक समय था जब दिवाली पर पटाखे जलाना भी सोच-समझकर होता था। आज तो पूरी कॉलोनियाँ दर रात तक डीजे, ढोल और आतिशबाजी के साथ गुंजती हैं, मानो किसी शादी में। मंडप का सार्वजनिक प्रसारण हो रहा हो। अब ये त्योहार उत्सव नहीं रह गए हैं, वे सांस्कृतिक शक्ति-प्रदर्शन बन गए हैं। सवाल यह नहीं है कि आप अपनी परंपराएँ क्यों जी रहे हैं, सवाल यह है कि आप उन्हें इस तरह क्यों जी रहे हैं कि आसपास के लोग असहज महसूस करने लगें।

इसका दूसरा पहलू यह है कि स्थिति को पलट कर देखो, तो हम तो आपस में ही इतना भेदभाव करते हैं कि दूसरों से सम्मान पाने की बात थोड़ी असहज लगती है। अमेरिका में बसे भारतीय प्रवासी भी अपनी क्षेत्रीय पहचानों में इतने उलझे रहते हैं कि ‘भारतीय’ पहचान कहीं पीछे छूट जाती है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण भारत से आए लोग अक्सर अपने रीति-रिवाज, भाषा और खानपान को लेकर इतने सजग और कभी-कभी आत्ममुग्ध रहते हैं कि दूसरे की सांस्कृतिक शैली को तुच्छ मानने लगते हैं। क्या हम तब भी यह दावा कर सकते हैं कि अमेरिका हमें एकसमान दृष्टि से देखेगा? जब हम अपने ही लोगों के साथ समानता नहीं निभा पाते, तो दूसरों से अपेक्षा रखना एकराफ़ा नहीं लगता। सांस्कृतिक असुरक्षा और गर्व के

बीच का अंतर बहुत महीन होता है। जब आप एक नई ज़मीन पर आते हैं, तो अपनी परंपराओं से जुड़ाव एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। लेकिन यह जुड़ाव कब असहिष्णुता में बदल जाए, इसका बोध आवश्यक है। संस्कृति को जीने का अधिकार सबको है, लेकिन उसमें दूसरों की जगह के लिए भी गुंजाइश होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमें अपनाया जाए, तो हमें यह भी दिखाना होगा कि हम अपनाते लायक हैं।

यह केवल इस देश के मूल्यों को स्वीकारो का तर्क नहीं है, बल्कि यह तय करने की बात है कि हम किस तरह के नागरिक बनना चाहते हैं। क्या हम ऐसे बनना चाहते हैं जो अपनी पहचान पर अड़े रहें, या ऐसे जो अपनी पहचान के साथ सौहार्द भी जी सकें?

हम यहाँ पहले मेहमान बनकर आए थे। धीरे-धीरे सदस्य बने। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि कुछ लोग खुद को बिना पूछे मेजबान समझने लगें हैं। यहीं से टकराव शुरू होता है और सामाजिक प्रतिक्रिया जन्म लेती है। समायोजन का मतलब खुद को मिटाना नहीं है, लेकिन यह भी नहीं कि हम उस देश की आत्मा को ही बदलने पर आमादा हो जाएँ जिसने हमें जगह दी।

मेरी और मेरी बेटी की सोच में अंतर है। शायद यह पीढ़ियों का फर्क है। लेकिन समाधान इन दोनों सोचों के बीच ही कहीं छिपा है। न अपनी पहचान छोड़नी चाहिए, न दूसरों की उपेक्षा करने की चाहिए। यही संतुलन हमें एक बेहतर प्रवासी और एक बेहतर इंसान बना सकता है। यही वह संयम और समझदारी है जिसकी किसी भी बहुसांस्कृतिक समाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है।

डॉ. पंकज राजवंशी, सिफ्टल (अमेरिका) में एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं

हर विद्यालय में सीखने का उत्सव - “प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान”



राजेश यादव

प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रदेश के हर बच्चे के उज्ज्वल भविष्य की नींव है। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को

सुदृढ़ करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग द्वारा चलाया जा रहा यह अभियान 90 दिनों तक चलेगा और 5 दिसम्बर तक राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में संचालित होगा। इसका प्रमुख लक्ष्य कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों में धारा प्रवाह पठन-पाठन की क्षमता विकसित करना है। भाषा और गणित की समझ को सरल व रोचक गतिविधियों के माध्यम से मजबूत किया जा रहा है ताकि बच्चों की नींव को पुख्ता बनाकर उन्हें आगे की पढ़ाई में आत्मविश्वास मिल सके।

अभिभावक भी बने सहभागी :-अभियान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ अभिभावकों को भी जोड़ा गया है। इसके लिए मेगा पीटीएम का आयोजन किया गया है ताकि अभिभावक बच्चों की प्रगति को स्वयं देख सकें और सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनें।

नवाचार की दिशा में बड़ा कदम :-इस अभियान को शिक्षा विभाग ने एक नवाचार के रूप में तैयार किया है। शिक्षकों को प्रशिक्षित कर विद्यार्थियों की कमजोरियों की पहचान की जा रही है और उन्हें व्यक्तिगत सहयोग देकर सुधार लाने की कोशिश की जा रही है। पिछले वर्ष संचालित प्रखर राजस्थान अभियान के सकारात्मक नतीजों को देखते हुए इस बार एआई आधारित ओरल रीडिंग प्लूएंगेसी आकलन भी लागू किया गया है। शिक्षा विभाग का मानना है कि यदि बच्चों का पठन-पाठन मजबूत होगा तो वे आगे की कक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करेंगे।

“नागौर हस्तशिल्प प्रदर्शनी-2025” का शुभारम्भ

■ प्रदर्शनी में स्थानीय उद्योग, हस्तशिल्प, दस्तकारों औ ओडीओपी उत्पादों को प्रदर्शित किया जा रहा है

■ “एक जिला एक उत्पाद” योजना के तहत चयनित पान मैथी के उत्पादन, सही लागत और जीआई टैग दिलाने के प्रयासों की जानकारी दी

से नौकरी करने के बजाय सफल उद्यमी बनकर रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर दिया। जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने “एक जिला एक उत्पाद” योजना के तहत चयनित पान मैथी के

उत्पादन, सही लागत और जीआई टैग दिलाने के प्रयासों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने स्थानीय उद्यमियों एवं हस्तशिल्पियों से समयानुकूल तकनीक अपनाने पर बल दिया। भारत सरकार

के जीएसटी विभाग के संयुक्त आयुक्त भारत सिंह ने हाल ही में जीएसटी दरों में की गई कमी से आमजन को मिलने वाले लाभों की जानकारी साझा की।

कार्यक्रम में खीवसर विधायक रेवन्त राम डांग्रा, जिला प्रमुख नागौर भागीरथ चौधरी, प्रधान प्रतिनिधि खीवसर जगदीश बिड़ियासर, लघु उद्योग भारती मेड़ता सिटी के रामवतार माहेश्वरी तथा हारालाल भाटी सहित विभिन्न एसोसिएशनों के पदाधिकारी एवं स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

राशिफल शुक्रवार 26 सितम्बर, 2025



पंडित अनिल शर्मा

संचार करेगा।

आज कुमार योग 9.37 से रात्रि 10.09 तक है। सवार्थ सिद्धि योग रात्रि 10.09 से सूर्योदय तक है। रवियोग रात्रि 10.09 से आरम्भ होगा।

आज भद्रा प्रातः 9.33 तक रहेगी। आज उपांग ललिता व्रत, ललिता पंचमी है।

श्रेष्ठ चौघडिया - चट-सूर्योदय से 7.50 तक, लाभ-अमृत 7.50 से 10.49 तक, शुभ 12.18 से 1.48 तक, चट 4.47 से सूर्यास्त तक

राहुकाल - 10.30 से 12.00 तक सूर्योदय 6.21 सूर्यास्त 6.18

आश्विन मास शुक्ल पक्ष, चतुर्थी तिथि, शुक्रवार विक्रम सम्पत् 2082, विशाखा नक्षत्र रात्रि 10.09 तक, विष्कुम्भ योग रात्रि 10.50 तक, विष्टि करण प्रातः 9.33 तक, चन्द्रमा दिम 3.24 से वृश्चिक राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-तुला, मंगल-तुला, बुध-कन्या, गुरु मिथुन, शुक्र-सिंह, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में

मेघ परिवार में आपसी सहयोग समन्वय बना रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग से महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो सकते हैं। दिन के मध्याह्न पश्चात अष्टम चन्द्र शुभ नहीं है।

वृष स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। मित्रों-रिश्तेदारों से चल रहे आपसी मतभेज समाप्त होंगे। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

मिथुन आज महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में उचित सोच विचार हो सकता है। महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में उचित परामर्श मिलेगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक कार्यों पर धन खर्च हो सकता है। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों-परिजन के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।

कन्या आर्थिक वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक सम्पर्क बनेंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा।

तुला आर्थिक वित्तीय मामलों में आ रही परेशानियां दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। संभावित धन प्राप्त होगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी।

वृश्चिक व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। घर-परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानि हो सकती है।

धनु आर्थिक-वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

मकर व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। सामूहिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार रहेगा।

कुंभ नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आशासन प्राप्त होगा। अटकें हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक परेशानियां दूर होगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज बनने काय विगड सकते हैं।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती मनाई

दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती पर ‘एकात्म मानवदर्शन’ पर व्याख्यान और रोजगार मेला आयोजित

जयपुर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति द्वारा उनकी 109वीं जयंती के अवसर पर गुरुवार को जयपुर स्थित थानक्या रेलवे स्टेशन परिसर में ‘एकात्म मानववाद से एकात्म मानवदर्शन की विकास यात्रा’ विषयक स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक एवं प्रदर्शनी स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं विचार

- वासुदेव देवनानी, अरुण जैन, गोपाल शर्मा सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे



देवनानी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक एवं प्रदर्शनी स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

गोष्ठी के साथ-साथ एक भव्य रोजगार मेले का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि विधायक गोपाल शर्मा विशिष्ट अतिथि रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख अरुण जैन ने मुख्य वक्ता के रूप में एकात्म मानववाद की अवधारणा पर विस्तृत व्याख्यान दिया। कार्यक्रम को अध्यक्षता उद्योगपति एवं समाजसेवी विजेंद्र सिंह ने की।

मुख्य वक्ता अरुण जैन ने अपने संबोधन में कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय सोच और संस्कृति के अनुकूल राजनीतिक और सामाजिक दर्शन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि उपाध्याय जी का दिया गया ‘एकात्म मानववाद’ केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि भारतीय समाज के समग्र विकास का मार्ग है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक गुरुजी ने इसे परिपूर्ण मानव का दर्शन कहा, वहीं दत्तोपंत

टेंगड़ी ने इसे एकात्म मानवदर्शन के रूप में देखा।

मुख्य अतिथि वासुदेव देवनानी ने कहा कि पंडित दीनदयाल जी ने विपरीत परिस्थितियों में भी सामान्य जीवन जीते हुए राष्ट्र को नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि वे संगठन के माध्यम से जनसेवा को सर्वोच्च मानते थे और जनसंघ में रहकर उन्होंने भारतीय राजनीति में वैचारिक संतुलन और नैतिक मूल्यों की नींव रखी।

विशिष्ट अतिथि गोपाल शर्मा ने कहा कि जब दीनदयाल जी जनसंघ के अध्यक्ष बने, तब उन्होंने देश में जनजागरण का कार्य शुरू किया और नई राजनीतिक दिशा दी। उन्होंने भारतीय राजनीति में सेवा, सादगी और सिद्धांत आधारित नेतृत्व की मिसाल पेश की।

कार्यक्रम के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह ने अपने उद्घोषण में कहा कि दीनदयाल उपाध्याय का स्वदेशी, रामराज्य और अंत्योदय का दर्शन आज भी भारत को

आत्मनिर्भर और विश्वगुरु बनाने की राह दिखाता है।

इस अवसर पर ‘दीनदयाल उपाध्याय की राजस्थान यात्राएं’ पुस्तक का विमोचन भी किया गया। सभी अतिथियों ने पंडित दीनदयाल राष्ट्रीय स्मारक परिसर और प्रदर्शनी का अवलोकन कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की।

समिति के अध्यक्ष प्रो. मोहनलाल छीपा ने समिति की गतिविधियों का परिचय देते हुए राज्य सरकार से दीनदयाल उपाध्याय बोर्ड गठन, विश्वविद्यालयों में शोध पीठ की स्थापना, दीनदयाल छात्रवृत्ति योजना, और पाठ्यक्रमों में उनके विचारों को शामिल करने जैसे सुझाव

रखे। सचिव प्रतापभानु सिंह शेखावत ने समिति की भावी योजनाओं की जानकारी दी, वहीं कोषाध्यक्ष गजेंद्र जानपुरिया ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन अखिल

महेश दलवी ने किया।

कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग के सहयोग से रोजगार मेले का आयोजन भी किया गया। इस मेले में 26 निजी कंपनियों ने भाग लिया और करीब 500 युवक-युवतियों ने पंजीकरण कराया। यह रोजगार मेला खासतौर पर धानक्या और आसपास के ग्रामीण युवाओं के लिए अवसर लेकर आया, जिससे उन्हें अपने ही क्षेत्र में नौकरी के अवसर मिलेंगे। नीरज कुमारवत ने इस रोजगार मेले के संयोजक की भूमिका निभाई।

इस आयोजन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक निम्बामाराम, प्रांत प्रचारक बाबूलाल, अनिल ओक, मूलचंद, क्षेत्र संघचालक रमेशचंद्र अग्रवाल, सांसद राव राजेन्द्र सिंह सहित अनेक गणमान्यजन, सामाजिक कार्यकर्ता एवं आमजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

जापान पर्यटन एक्सपो आइची में राजस्थान मंडप का उद्घाटन

जयपुर/टोक्यो । जापान के टोक्यो शहर में आयोजित जापान पर्यटन एक्सपो आइची में सहभागिता करने के लिए टोक्यों पहुंची राजस्थान पर्यटन आयुक्त रुक्मणी रियाड़ और टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास की पर्यावरण एवं वाणिज्य मंत्री देबजानी चक्रवर्ती ने गुरुवार को उक्त एक्सपो में राजस्थान मंडप का उद्घाटन किया।

- राजस्थान पर्यटन आयुक्त रुक्मणी रियाड़ और टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास की पर्यावरण एवं वाणिज्य मंत्री देबजानी चक्रवर्ती ने जापान पर्यटन एक्सपो आइची में किया राजस्थान मंडप का उद्घाटन

ट्रैवल एजेंट) और जापान राष्ट्रीय पर्यटन संगठन (जेएनटीओ) के अध्यक्ष और अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत चर्चा में भाग लिया और राजस्थान के आकर्षक पर्यटन स्थलों

और उत्पादों के संबंध में जानकारी दी और फ़िल्म के माध्यम से एक प्रस्तुति दी।

राजस्थान के पर्यटन आकर्षणों और उत्पादों के जीवंत प्रदर्शन के साथ, जापान पर्यटन एक्सपो आइची में राजस्थान पर्यटन स्टैंड आकर्षण का केंद्र बन गया है। स्टैंड पर लाइव हस्तशिल्प प्रदर्शन बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित कर रहा है।

इस दौरान जापानी मीडिया से भी बातचीत की गई तथा राजस्थान पर्यटन के भव्य स्वरूप और यहां की पर्यटन विशेषताओं से अवगत कराया गया। इसके साथ ही व्यावसायिक बैठकें भी आयोजित की गईं।

जापानी ब्लॉगर मधु राजस्थानी सदस्यों के साथ राजस्थान स्टैंड पर उपस्थित रही जहां उनकी लोक प्रस्तुति संपन्न हुई है।

तीन आरोपी गिरफ्तार

जयपुर। जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल जिला स्पेशल टीम (क्राइम ब्रांच सीएसटी) ने भांकोटा थाना इलाके में कार्रवाई करते हुए आगरा से प्रतिबंधित नशीली दवाइयों और टैबलेट्स मंगवाकर जयपुर में सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 37 हजार 410 टैबलेट्स और केप्सूल के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने बताया कि सीएसटी ने भांकोटा थाना इलाके में ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित नशीली दवाइयों और टैबलेट्स मंगवाकर जयपुर में सप्लाई करने वाले गिरोह के शांति बंदमाश संपत सिंह शेखावत निवासी जयसिंहपुरा, अंकुश अग्रवाल और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर निवासी अभिराम सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से प्रतिबंधित नशीली दवा अल्फ्राजोलम और ट्रामाडोल के कुल 37 हजार 410 केप्सूल और टैबलेट्स बरामद किए हैं।

चारदीवारी में हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश

- नगर निगम की ओर से समय-समय पर सिर्फ नोटिस जारी करने पर नाराजगी जताई

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर की चारदीवारी के भीतर हुए अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के बजाए नगर निगम की ओर से समय-समय पर सिर्फ नोटिस जारी करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि जिन भवन मालिकों को अवैध निर्माण के नोटिस जारी किए जा चुके हैं, उन बिल्डिंगों को स्थाई रूप से सील कर दो माह में ध्वस्त करने की कार्रवाई पूरी की जाए। अदालत ने निगम आयुक्त को कहा है कि संबंधित उपायुक्त और जिन अधिकारियों से नोटिस देने के बाद कार्रवाई नहीं की, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। अदालत ने कहा है कि यदि इन अफसरों को तबादला भी हो चुका है तो डीएलबी सचिव आदेश की पालना सुनिश्चित करें। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित को खंडपीठ ने यह आदेश जितेंद्र कुमार साधवानी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए

दिए। अदालत ने कहा कि नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत निगम के अधिकारियों के पास कार्रवाई करने की शक्तियां हैं। इसके बावजूद उन्होंने समय-समय पर अंतिम नोटिस के नाम पर कागजी कार्रवाई की और उसके बाद प्रभावी कदम नहीं उठाया।

अदालत ने कहा कि नगर निगम की ओर से प्रभावी कदम नहीं उठाने से पूरी चारदीवारी के भीतर अवैध इमारतें बन गई हैं। अवैध बिल्डिंग पूरे शहर और समाज के लिए खतरा बन गई है और इसने चारदीवारी के विरासत मूल्यों के बर्बाद कर दिया है। वहीं निगम की इस कार्यप्रणाली से अन्य लोग भी अवैध

निर्माण के लिए प्रोत्साहित होते हैं। ऐसे में अधिकारियों को इन अवैध निर्माणों पर आंख मूंदकर बैठने और नोटिस जारी करने के छह माह बाद भी हिलाई बरतने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संजय जोशी ने कहा कि शहर के परकोटे के भीतर युद्ध स्तर पर अवैध निर्माण हो रहे हैं। भवन मालिकों ने न तो नगर निगम से निर्माण की स्वीकृति ली है और ना ही नक्शे पास कराए हैं। वहीं कई लोगों ने अपने रिहायशी मकानों को तोड़कर बिना पार्किंग छोड़े बहुमंजिला व्यावसायिक निर्माण कर लिए हैं। इस संबंध में निगम में कई बार शिकायत की, लेकिन निगम ने उन्हें छह माह के अंतराल में सिर्फ नोटिस जारी किए। जिसके चलते भवन मालिक ने निर्माण पूरा कर लिया। वहीं निगम की ओर से जवाब पेश कर माना गया कि अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस जारी किए गए थे।

शाहरुख और दीपिका के खिलाफ कार्रवाई पर रोक जारी

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने खराब कार की मार्केटिंग करने से जुड़े मामले में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के खिलाफ भरतपुर के मथुरा गेट थाने में दर्ज एफआईआर में कार्रवाई पर लगी रोक को जारी रखा है। इसके साथ ही अदालत ने कार कंपनी और शिकायतकर्ता को अपना विवाद आपसी सहमति से तय करने को कहा है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण सहित अन्य की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता का विवाद अपनी जगह है, लेकिन उसने कंपनी के ब्रांड एंबेसडर के खिलाफ कार्रवाई क्यों कि है। कंपनी के साथ मिलकर सहमति से मामला सुलझाया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पैवैची करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता यविक राज बाजवा और माधव मित्र ने अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता ने कार खरीदने के बाद उसे तीन साल तक करीब 67 हजार किलोमीटर चलाया और उसके बाद एफआईआर दर्ज कराई।

- कार कंपनी और शिकायतकर्ता आपस में सहमति से करें मामले का निस्तारण

मामले में फिल्मी कलाकार याचिकाकर्ताओं पर कोई स्पष्ट आरोप नहीं है। वे कार के ब्रांड एम्बेसडर हैं और उन्होंने सिर्फ कार का विज्ञापन किया था।

याचिकाकर्ता दीपिका पादुकोण तो शिकायतकर्ता के वाहन खरीदने के बाद इस ब्रांड से जुड़ी है। इसके अलावा हर वाहन की परफॉर्मंस उसके चलाने के तरीके पर निर्भर करती है। यदि शिकायतकर्ता को कार की परफॉर्मंस को लेकर कोई शिकायत भी थी तो इसमें कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है। शिकायतकर्ता इसे उपभोक्ता अदालत में परिवाद दायर कर चुनौती दे सकता था।

इसके बावजूद भरतपुर की निचली अदालत के पीठासीन अधिकारी ने बिना विधिक मस्तिष्क का उपयोग किए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में उनके खिलाफ दर्ज

एफआईआर को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने गत सुनवाई पर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर में आगामी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। भरतपुर के वकील कीर्ति सिंह ने इस्तफासे के जरिए मथुरा गेट थाने में गत दिनों एफआईआर दर्ज कराई थी।

जिसमें कंपनी के एमडी अनसो किश, निदेशक और सीईओ तरुण गर्ग, शाहरुख खान व दीपिका पादुकोण सहित अन्य को आरोपी बनाते हुए कहा गया था कि उसने जून, 2022 में 23 लाख 97 हजार रुपये में एक कंपनी की कार खरीदी थी। हाईवे पर कार चलाने के दौरान ओवरटेक करते समय कार फिकअप नहीं लेती और उसका सिर्फ आपीएम ही बढ़ता है। कार के ओडोमीटर में माल फंक्शन लिखा आने का साइन नजर आता है। वहीं तेज चलाने पर कार वाइब्रेट होने लगती है। एफआईआर में यह भी कहा गया कि जब शिकायत दी गई तो कार एजेंसी संचालक ने इसे कार निर्माण में दोष बताया। अपराध में कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ दोनों फिल्मी कलाकार भी बराबर के आरोपी हैं।

यू.ई.एम. का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सम्पन्न



अनुप्रयुक्त विज्ञान के विविध अनुप्रयोगों पर प्रकाश डालते हुए अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए।

जयपुर। सम्मेलन में दोनों मोड में दुनिया भर से 150 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें शोध विद्वान, शिक्षाविद और उद्योग पेशेवर शामिल थे। उद्घाटन समारोह में प्रो. बनानी चक्रवर्ती (कुलाधिपति, यूईएम जयपुर), प्रो. (डॉ.) सत्यजीत चक्रवर्ती (प्रो-वाइस चांसलर, यूईएम जयपुर), प्रो. (डॉ.) प्रदीप कुमार शर्मा (रजिस्ट्रार, यूईएम जयपुर), के साथ साथ यूईएम जयपुर के एसोसिएट डीन देश के विभिन्न हिस्सों से अन्य प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इसके अलावा, लगभग

101 शिक्षाविदों ने कम्यूटेेशनल और अनुप्रयुक्त विज्ञान के विविध अनुप्रयोगों पर प्रकाश डालते हुए अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए।

समापन सत्र 21 सितंबर 2025 को शाम 5:00 बजे आयोजित किया गया, जहाँ संयोजक डॉ. प्रफुल्ल छाबड़ा और डॉ. तरुण शर्मा ने सम्मेलन पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रतिभागियों ने उपयोगी चीजें और मूल्यवान नेटवर्किंग अवसरों के लिए अपनी सराहना व्यक्त की। कार्यक्रम का समापन संयोजक डॉ. प्रफुल्ल छाबड़ा द्वारा औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

नाहरगढ़ अभयारण्य की मौजूदा सीमाओं में परिवर्तन पर रोक, मांगा जवाब

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नाहरगढ़ अभयारण्य की मौजूदा सीमाओं में परिवर्तन करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि इसमें ईको सेंसिटिव ज़ोन और वर्णित क्षेत्र भी शामिल रहेगा। इसके साथ ही अदालत ने मामले में पर्यावरण मंत्रालय, राज्य के मुख्य सचिव, सीएसएस वन, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड और पीसीसीएफ सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। वहीं अदालत ने मामले में उठाए गए मुद्दे पर केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को शपथ पत्र पेश कर करने के आदेश देते हुए पीसीसीएफ का हलफनामा भी मांगा है। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित को खंडपीठ ने यह आदेश नाहरगढ़ वन एवं वन्य जीव सुरक्षा एवं सेवा समिति की जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई की करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता केसी शर्मा ने अदालत को बताया कि एन-जीओ के 16 दिसंबर 2024 के आदेश की आड में नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य का संशोधित नक्शा तैयार किया जा रहा है।

जिसमें मिलीभगत कर वर्णित क्षेत्र में शामिल होने वाले गांवों की भूमि को शामिल नहीं किया गया है।

इस कार्रवाई में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों की भी अवहेलना की जा रही है। इस दौरान राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सिफारिश लिए बिना ही अभयारण्य की सीमाओं में बदलाव किया जा रहा है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि नाहरगढ़ अभयारण्य की सीमा पर चल रही गैर वाणिजी गतिविधियों और व्यावसायिक गतिविधियों को फायदा पहुंचाने के लिए वन विभाग की ओर से यह कार्रवाई की जा रही है। याचिका में भी कहा गया कि अभयारण्य की सीमाओं में संशोधन की कार्रवाई से अभयारण्य को नुकसान हो रहा है और ईको सेंसिटिव ज़ोन भी प्रभावित हो रहा है। जिन पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने अभयारण्य की मौजूदा सीमाओं में बदलाव करने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है और केन्द्र व राज्य सरकार के अफसरों से शपथ पत्र पेश करने को कहा है।

सार-समाचार

भारत रत्न भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय का हुआ उद्घाटन



जयपुर। वार्ड 31 के लोकप्रिय पार्षद लादूराम दुलारिया द्वारा अथक प्रयासों से नगर निगम से लगभग 26 लाख रुपये स्वीकृत करवा के वार्ड 31 में भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय का निर्माण करवाया गया। जिसका उद्घाटन क्षेत्रीय पार्षद लादूराम दुलारिया द्वारा फीता काटकर किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री राजीव अरोड़ा, पीसीसी महामंत्री विक्रम सिंह शेखावत, पूर्व पीसीसी महामंत्री गिरांग गंग, पूर्व उपाध्यक्ष विप्र कल्याण बोर्ड मंजु शर्मा , पीसीसी सदस्य महेंद्र सिंह खेड़ी , जगदीश शर्मा ब्लॉक अध्यक्ष हरेंद्र पाल सिंह जादौन, शहर उपाध्यक्ष पार्षद नसरीन बानो , रैगर समाज के अध्यक्ष महेंद्र पाल सिंह जादौन ब्लॉक अध्यक्ष रैगर समाज के कमलेश कुमार व उनकी कार्यकारिणी , वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुशील शर्मा लक्ष्मण सिंह कैलाश गुरुजी रामकुमार शर्मा , ऑंकार मल, देवीलाल वर्मा, सहित अनेक पार्षद प्रत्याशी वार्ड अध्यक्ष इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। संगठन महामंत्री मनोज अमन ने बताया कि आये हुए सभी अतिथियों ने पार्षद लादूराम दुलारिया द्वारा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों की भूरि भूरि प्रशंसा की और क्षेत्र के नागरिकों से अपील की कि भविष्य में आप इन्हें पुनः जिताकर नगर निगम में भेजें जिससे आपके क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके ।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा, प्रदेश मंत्री स्टेफी चौहान, प्रदेश कार्यलय प्रभारी मुकेश पारीक, पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष सुमन शर्मा, भाजपा प्रवक्ता अपूर्वा सिंह, प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। भाजपा प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद का दर्शन और अंत्योदय का विचार अंदर भारत के विकास पथ को दिशा देता रहेगा। उनका विचार था कि संदेव पंक्ति में खड़े व्यक्ति ही वास्तविक राष्ट्र निर्माण है। उनके सिद्धांत आज भी सरकार की समावेशी विकास की नीति में पूर्ण रूप से समाहित है। इस दौरान भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं ने भी पुष्प अर्पित किए।

पटवारी व दलाल को पन्द्रह हजार रुपये की रिश्तत लेते गिरफ्तार

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टॉक टीम ने कार्रवाई करते हुए कार्यलय तहसील गद्दी जिला के टॉक पटवारी नरेंद्र बैरवा और दलाल मोहम्मद को पन्द्रह हजार रुपये की रिश्तत लेते गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रिम्ता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी टीम टॉक को परिवारी ने शिकायत दी कि उसके पुत्री-पुत्रो के नाम से खरीदी भूमि का नामांतरण खोलने की एवज में आरोपित पटवारी नरेंद्र बैरवा तीस हजार रुपये की रिश्तत मांग की जा रही है। जिस पर एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया। जहां आरोपित पटवारी ने तीस हजार रुपये की रिश्तत मांग की। जिस पर एसीबी टोक टीम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झाबर मल ने ट्रेप की कार्रवाई को अंजाम दिया। ट्रेप के दौरान पटवारी ने अपनी उपस्थिति में अपने परिचित मोहम्मद नसीम (दलाल) को पन्द्रह हजार रुपये की रिश्तत परिवारी से दिलाई गई। इस दौरान एसीबी ने कार्रवाई करते हुए पटवारी और दलाल को रिश्तत मामले में गिरफ्तार किया।

मुख्यमंत्री ने त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा की

मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी मंदिर में दर्शन किए

बाँसवाड़ा/जयपुर, 25 सितम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को बाँसवाड़ा के तलवाड़ा स्थित शक्ति पीठ त्रिपुर सुंदरी मंदिर में दर्शन तथा विधि-विधान से पूजा अर्चना की। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।

■ मुख्यमंत्री ने नापला हैलीपैड पर कहा कि प्रधानमंत्री ने राजस्थान को जो सौगातें दी हैं, उससे प्रदेश का विकास होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बाँसवाड़ा के तलवाड़ा में त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा की।

मंदिर दर्शन से पूर्व मुख्यमंत्री ने नापला हेलीपैड पर मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के प्रति जनता में विशेष आकर्षण, लगाव और विश्वास है, इसलिए इतनी विशाल सभा का आयोजन आज नापला में हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जब भी राजस्थान आते हैं, प्रदेश को सौगातें

देते हैं। आज उन्होंने प्रदेश के लिए लगभग 1 लाख 8 हजार करोड़ रुपये के कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। साथ ही, 15 हजार से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए।

शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने वागड़ क्षेत्र में आज माही बाँसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी है। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा।

‘सरकार मुझे जेल भेजने की तैयारी में है’

लदाख, 25 सितंबर। लदाख में भड़की हिंसा पर जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सरकार पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो सरकार की दिक्कतें उनकी आजादी से कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगी।

वांगचुक ने गुरुवार को गुहमंत्रालय के उस बयान को खारिज किया जिसमें बुधवार की हिंसा के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार बलि का बकरा तलाश रही है जबकि असली समस्या को नजरअंदाज कर रही है।

भाजपा के सांसदों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) जहाँ एक ओर नीतीश कुमार साफ-सुथरे शासन पर जोर दे रहे हैं, वहीं भाजपा की आंतरिक कलह सामने आ रही है, जिससे बिहार में एनडीए का चुनावी गणित काफी कमजोर दिख रहा

वांगचुक के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) एजूकेशनल एंड कल्चरल मुवमेंट आफ लदाख का पंजीकरण प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। उल्लेखनीय है कि सोनम वांगचुक लदाख को संविधान

है। पार्टी नेतृत्व के सामने दोहरी चुनौती है, सहयोगियों को शांत करना और अपने ही वरिष्ठ नेताओं को चुनावी मैदान में उतरने के लिए मनाना। जैसी स्थिति है, एनडीए इस चुनावी मौसम में सवालों से घिरा हुआ है, जवाबों से नहीं।

की छठी अनुसूची में शामिल करने तथा उसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर पिछले कुछ दिनों से हड़ताल कर रहे थे। लेह में बुधवार की हिंसा भड़कने के बाद उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली थी।

अमेरिका विश्व ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) यह प्लेटफॉर्म युवाओं का ध्यान आकर्षित करने और उन पर प्रभाव डालने में इतना सफल हो गया था कि अमेरिकियों को खतरा महसूस होने लगा और उन्होंने इसे रोकने की कोशिश की। पूर्व के बाइडन प्रशासन ने कंपनी को आदेश दिया था कि वह अमेरिका में अपनी संपत्तियाँ किसी अमेरिकी समूह को बेच दे। सरकार टिक टॉक के संचालन वाले मूल एल्गोरिदम को भी हासिल करना चाहती थी।

ट्रंप के सत्ता में आने के बाद उन्होंने भी यही नीति जारी रखी और एक समयसीमा तय की कि कंपनी को या तो अपनी अमेरिकी संपत्तियों का स्वामित्व अमेरिकियों को सौंपना होगा, या फिर अमेरिका में अपना काम बंद करना होगा। चीन ने इस अमेरिकी कदम का विरोध किया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला दिया, जबकि चीन में खुद ऐसी स्वतंत्रता नहीं है।

विवाद के चलते चीन और अमेरिका ने कंपनी के भविष्य को लेकर बातचीत शुरू की। चीन ने टिक टॉक की अमेरिकी संपत्तियों को बेचने के विचार का विरोध किया, क्योंकि स्पष्ट रूप से वह अमेरिकी बाज़ार तक अपनी पहुँच खोने को लेकर चिंतित था।

स्कूल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) शर्त पर दी कि विद्यार्थियों को कोई अनुविधान न हो। उच्च न्यायालय ने स्कूल मैदान में रामलीला के आयोजन पर रोक लगा दी थी।

शीर्ष अदालत ने आदेश पारित करते हुए इस दलील पर भी गौर किया कि स्कूल के मैदान का उपयोग लगभग 100 वर्षों से रामलीला समारोहों समेत अन्य धार्मिक उत्सवों के लिए किया जाता रहा है।

पीठ ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता के वकील से पूछा, "यह पिछले 100 सालों से होता आ रहा है। आपने आखिरी समय में अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाया? आपको पहले से जाकर प्रशासन से व्यवस्था करने के लिए कहने से किसने रोका? आप न तो छात्र हैं और न ही किसी छात्र के अभिभावक... आप संपत्ति के मालिक नहीं हैं... आप जनहित याचिका दायर कर सकते थे, लेकिन आपको किसने रोका?"

दोनों देशों ने कंपनी के भविष्य को लेकर बातचीत जारी रखी, लेकिन ट्रंप की टैरिफ नीति के हमलों के बाद ये वार्ताएँ रुक गईं। बाद में जब चीन ने दुर्लभ खनिज जैसे अहम कच्चे माल की आपूर्ति रोकने जैसी गंभीर धमकियाँ दीं तो बातचीत फिर शुरू हुई।

अमेरिकी बाज़ार में टिकटॉक को बंद करने की धमकी देकर ट्रंप प्रशासन ने सीधे अमेरिकी स्वामित्व के तहत इसे चलाने की एक योजना तैयार की है।

भूपेन्द्र ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) अनुभव है। वहीं, बिप्लव देब का अनुभव पूर्वोत्तर राज्यों से बंगाल की राजनीति को मजबूत करेगा।

बिहार के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी जबकि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल को सह-प्रभारी बनाया है।

तमिलनाडु में भाजपा सांसद बैजयंत पांडा को प्रभारी और मुरलीधर मोहोले को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है।

(प्रथम पृष्ठ का शेष) सामर्थ्य का एक नया अध्याय लिखा गया है।

उन्होंने कहा कि देश में पूर्ववर्ती सरकारों ने बिजली के महत्व पर ध्यान नहीं दिया। आजादी के 70 साल बाद भी देश के 18 हजार गांवों में बिजली का खंभा तक नहीं लगा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार स्वच्छ ऊर्जा के अभियान को एक जन-आंदोलन बनाकर काम कर रही है। किसानों को सस्ती बिजली मिल सके, इसके लिए पीएम-कुसुम योजना के तहत खेतों में भी सोलर पंप लगाए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर उन्हें स्मरण करते हुए कहा कि उनका अंत्योदय का सिद्धान्त आज हमारा मिशन बन चुका है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ऊर्जावान नेतृत्व में राजस्थान स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर पहुँच गया है। पीएम-कुसुम योजना के तीनों चटकों में राज्य में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। कुसुम योजना के घटक-ए में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है और राज्य के 22 जिलों में

‘बाँसवाड़ा की धरती पर ...

- प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश को विकास की राह पर ले जाने में राजस्थान बड़ी भूमिका निभा रहा है।
- प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि प्र.मंत्री के नेतृत्व में राजस्थान स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान पर पहुँच गया है।
- कार्यक्रम की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने पं. दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने साफा पहनाकर और विजय स्तंभ का चित्र प्रदान कर प्रधानमंत्री का स्वागत किया।

किसानों को दिन के समय बिजली मिलनी शुरू हो चुकी है।

मुख्यमंत्री ने 1 लाख 8 हजार करोड़ रुपये की ऐतिहासिक सौगातें राजस्थान को देने के लिए प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान 2 अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र भी प्रतीक रूप में प्रदान किए। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीकानेर-दिल्ली कैंट बंदे भारत एक्सप्रेस, जोधपुर-दिल्ली कैंट बंदे भारत एक्सप्रेस एवं उदयपुर सिटी-चंडीगढ़

एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्व. पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी का साफा पहनाकर और आदिवासी सम्मान का प्रतीक तिर-कमान भेंट कर स्वागत किया।

कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, सांसद मदन राठौड़, केन्द्र एवं राज्य सरकार के मंत्रीगण सहित, सांसद एवं विधायकगण और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

अगले लोकसभा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हुई "सिंधु जल संधि" एक ऐतिहासिक जल-बंटवारा समझौता था। लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने यह संधि निर्लंबित कर दी थी, और सरकार ने दृढ़तापूर्वक स्पष्ट किया था कि "पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते।"

तब से भारत सरकार सिंधु जल के अपने हिस्से के उपयोग के लिए एक विस्तृत योजना पर काम कर रही है। इसे साकार करने के लिए इंटर-बेसिन सिंधु जल ट्रांसफर योजना के तहत एक महत्वाकांक्षी परियोजना पर विचार किया गया है, जिसकी निगरानी उच्च स्तर पर की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, इस परियोजना का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है- 14 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण। इसके लिए पर्वतीय चट्टानों का विस्तृत अध्ययन आवश्यक है। यदि चट्टानें कमजोर पाई जाती हैं, तो

सुरंग पाइपों के माध्यम से बनाई जाएगी। इसका निर्माण कार्य डीपीआर मिलने के बाद शुरू किया जाएगा।

सुरंग निर्माण के लिए "टनल बोरिंग मशीन" और "रॉक शील्ड टैक्नालजी" के उपयोग का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि गति और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित की जा सकें। यह सुरंग जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में स्थित "उझ मल्टी परपज़ प्रोजेक्ट" से भी जोड़ी जाएगी, जिससे रावी की सहायक नदी उझ से ब्यास बेसिन में जल स्थानांतरित किया जा सकेगा।

इस सुरंग के पूरा होने से रावी-ब्यास-सतलुज प्रणाली को सिंधु बेसिन से जोड़ा जा सकेगा, जिससे भारत अपने हिस्से के जल का अधिकतम उपयोग कर सकेगा। सूत्रों का अनुमान है कि इसका निर्माण तीन से चार वर्षों में पूरा हो जाएगा और यह कार्य 2028 तक तैयार हो सकता है। इसकी अनुमानित लागत करीब 4,000 - 5,000 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

**MARUTI SUZUKI**

CELEBRATIONS JUST GOT BIGGER.

WITH GST BENEFITS + LIMITED PERIOD FESTIVE OFFERS*

	PRICE REDUCTION OF UP TO*	NOW STARTING AT*	ADDITIONAL FESTIVE OFFERS OF UP TO*
FRONX	₹ 1 12 600	₹ 6 84 900	₹ 70 000
GRAND VITARA	₹ 1 07 000	₹ 10 76 500	₹ 1 29 100 + 5 Year Extended Warranty
BALENO	₹ 86 100	₹ 5 98 900	₹ 72 500
IGNIS	₹ 71 300	₹ 5 35 100	₹ 62 500
INVICTO	₹ 61 700	₹ 24 97 400	₹ 1 40 000
XL6	₹ 52 000	₹ 11 52 300	₹ 25 000
JIMNY	₹ 51 900	₹ 12 31 500	₹ 1 00 000



SCAN TO CONNECT
TO A SHOWROOM
NEAR YOU



*FESTIVE OFFERS VALID TILL 30TH SEP ONLY

UP TO 100% WAIVER ON CAR LOAN PROCESSING FEE (ONLY TILL 30TH SEP)##

E-BOOK TODAY @
WWW.NEXAEXPERIENCE.COM

Contact us at
1800-200-[6392]
1800-102-[6392]

For detailed T&C kindly visit your nearest dealership. Features and accessories shown may not be a part of the standard fitment. Black glass shade on the vehicle is due to the lighting effect. Images used are for illustration purposes only. All offers are brought to you by NEXA dealers only. Offers and features may vary subject to the model and variant purchased. *The mentioned offers include "Consumer Offer + Booking offer + Exchange Bonus + Rural offer", and may vary from city to city. Please contact nearby dealership for more details. Maruti Suzuki reserves the right to withdraw offers at any point in time without any advance notice. All offers are applicable till 30th September '25 or till stocks last. Maruti Suzuki Smart Finance is now available pan India. Maruti Suzuki Subscribe is available only in selected cities. ##Offers include consumer offer, exchange bonus and institutional or rural offers (wherever applicable) on select models/variants. Finance is at the sole discretion of the financier by selected finance partners. *Prices and savings mentioned above are for select variants and may vary across cities/ variants.

●●●●

⊕

●●●●

⊕

●●●●

⊕

●●●●

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस प्रलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, बीकानेर कार्यालय : कुम्हाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रतृ भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्स्टीटयल एरिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908